

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1245
10 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नीट पीजी 2025 के लिए कटऑफ कम करने का प्रस्ताव

1245 श्री पी.पी. सुनीर:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में हजारों स्नातकोत्तर सीटें रिक्त रहने के कारण नीट पीजी 2025 की कट-ऑफ शून्य प्रतिशत स्तर तक घटाने का निर्णय लिया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में रिक्त सीटों की संख्या क्रमशः कितनी-कितनी है;
- (घ) क्या यह सच है कि निजी मेडिकल कॉलेजों में अधिकांश सीटें रिक्त पड़ी हैं, क्योंकि वहाँ करोड़ों रुपये फीस के रूप में लिए जाते हैं जिसे अधिकांश अभ्यर्थी वहन करने में असमर्थ हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री
(श्रीमति अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) की चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए परामर्श आयोजित करती है। एमसीसी द्वारा आयोजित एनईटी पीजी परामर्श में अखिल भारतीय कोटा की 50% सीटें और देश भर के केंद्रीय/मानित विश्वविद्यालयों की 100% सीटें शामिल होती हैं। राज्य कोटा पीजी सीटों के लिए परामर्श संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आयोजित किया जाता है और निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए परामर्श राज्य परामर्श प्राधिकरणों के दायरे में आता है।

अर्हता प्रतिशत को संशोधित करने का निर्णय एमसीसी द्वारा दूसरे दौर की काउंसलिंग पूरी हो जाने के बाद लिया गया है जिसमें यह सूचित किया गया है की एमसीसी द्वारा काउंसलिंग के लिए प्रस्तावित 29,476

सीटों में से 9,621 सीटें रिक्त रह गई थीं। इसके अतिरिक्त, चूंकि 50% सीटों के लिए काउंसलिंग संबंधित राज्य प्राधिकरणों द्वारा आयोजित की जाती है, इसलिए यह अनुमान लगाया गया कि दो दौर के बाद लगभग 20,000 सीटें (डीएनबी सीटों सहित) रिक्त रह गईं। अतः उन पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्षों जो सीटों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने में प्रभावकारी सिद्ध हुए, के अनुरूप सरकार ने पीजी काउंसलिंग हेतु पात्रता के लिए अर्हता प्रतिशत को कम कर दिया ताकि महत्वपूर्ण पीजी सीटें खाली न रह जाएं।

नीट पीजी 2025 के लिए संशोधित अर्हता प्रतिशत इस प्रकार हैं:

- आयु वर्ग (अनारक्षित) श्रेणी: पात्रता 7 परसेंटइल से अधिक तक सीमित कर दी गई है।
- आयु वर्ग (अना.दिव्यांग-पीडब्ल्यूडी) श्रेणी: पात्रता 5 परसेंटइल से अधिक तक सीमित कर दी गई है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियां: सभी उम्मीदवार योग्य घोषित किए गए हैं।

सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल पाठ्यक्रमों की शुल्क संरचना राज्यों के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है और संबंधित राज्य शुल्क नियामक प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित की जाती है। सुलभता बढ़ाने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शुल्क संरचना में सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा, निजी चिकित्सा संस्थानों और मानित विश्वविद्यालयों में 50% सीटों के लिए शुल्क और अन्य शुल्कों के निर्धारण हेतु दिशानिर्देश राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (i) के अंतर्गत तैयार किए गए थे और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा 03.02.2022 को जारी किए गए थे। हालांकि, इन दिशानिर्देशों को विभिन्न न्यायालयों में चुनौती दी गई है और फिलहाल मामला विचाराधीन है।
